RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 27 NOVEMBER TO 03 DECEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 14 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

एनजीटी ने दोषी माना, पानीपत रिफाइनरी पर 659 करोड़ जुर्माने की सिफारिश Page 2

गूगल माई बिजनेस से आसानी से ऑनलाइन स्टोर खोल सकेंगे दुकानदार Page 3

सबसे सस्ती कार Kwid में अब जल्द मिलेगा Bs6 इंजन Page 6

editoria!

बाजार की उलटबांसी

अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले इन दिनों उलझन में हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि अभी जब देश की आर्थिक विकास दर को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं तो शेयर बाजार उछालें क्यों मार रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट साल की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर चली गई है। रेटिंग एजेंसियां आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा रही हैं। लेकिन बीएसई और एनएसई का ग्राफ बीच के छोटे-मोटे उतार के बावजूद लगातार ऊपर की ओर है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2019 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाकर 5.6 फीसदी कर दिया है। 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21' में उसने 2020 और 2021 में ग्रोथ रेट क्रमशः 6.6 फीसदी और 6.7 फीसदी होने की उम्मीद जताई है, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा है कि बीते दिनों की तुलना में आर्थिक सक्रियता कम ही रहेगी। मूडीज ने भारत सरकार की सॉवरेन रेटिंग्स को भी न्यूट्रल से बदलकर नकारात्मक कर दिया था। सवाल है कि घरेलू और विदेशी निवेशक क्या रेटिंग एजेंसियों को गंभीरता से नहीं लेते, या फिर एजेंसियों का आकलन संदिग्ध है? हकीकत यह है कि शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का आईना समझने की धारणा ही गलत है। आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों का शेयर बाजार पर असर जरूर पड़ता है लेकिन शेयर बाजार के चढ़ने-उतरने की वजहें अक्सर अलग होती हैं। शेयरों पर कई स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय तत्वों का प्रभाव तो पड़ता ही है, खास कंपनियों से जुड़ी खबरें भी इसमें इंजन की भूमिका निभाती हैं। अभी जो तेजी दिखाई पड़ रही है, उसका फैलाव सारे शेयरों तक नहीं है। कुछ खास शेयर ही ऐसे हैं, जो लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी सरकारी कंपनियों में विनिवेश का फैसला भी शेयर बाजार के लिए खुशहाली लेकर आया है। शेयर बाजार के खिलाड़ी मानकर चल रहे हैं कि भारतीय इकॉनमी का सबसे बुरा दौर बीत चुका है। किसी बड़े बदलाव के संकेत भले ही न हों पर उन्हें इसकी रिकवरी का भरोसा है। यह शेयर बाजार का चरित्र है कि जब मुनाफे कम हो रहे होते हैं तो स्थानीय म्यूचुअल फंडों और ग्लोबल निवेशकों के जरिए चुनिंदा शेयरों में गति आती रहती है।बाजार कई चीजों पर पैनी नजर रखता है। जैसे पिछले साल लगा कि एनबीएफसी संकट बहुत ज्यादा गहरा है, लेकिन अब यह एहसास होने के बाद कि नीति-निर्माता उनके बारे में सोच रहे हैं, शेयर बाजार इस तरफ से निश्चिंत दिख रहा है। वैसे, बाजार की यह तेजी सिर्फ भारत में नहीं है। कई और शेयर बाजार भी रिकॉर्ड स्तर पर हैं। पूरी दुनिया में और भारत में भी नरम ब्याज दरों की नीति ने उत्साह बढ़ाया है। हालांकि यहां यह जोड़ना जरूरी है कि शेयर बाजार लंबे समय तक बुनियादी आंकड़ों के खिलाफ नहीं जा सकते। बाजार में तेजी लंबी चले, इसके लिए अच्छी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना जरूरी है।

अगर टोल प्लाजा पर Fastag स्कैनर हुआ खराब, तो कैसे कटेगा टोल

जीरो की रसीद भी कटेंगी, वजन के अनुसार रंग तय

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने 01 दिसंबर 2019 से गाड़ियों पर Fastag लगाना अनिवार्य कर दिया है और सरकार इसे कई जगहों पर मुफ्त बेच भी रही है। फास्टैग के जरिये लोग अब टोलप्लाजा पर कैश की बजाय वॉलेट के जरिये पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए कई टोलप्लाजा पर Fastag को स्कैन करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (RFID) लगाई जा रही हैं। वहीं अगर आप भी टोल प्लाजा से गुजरते हैं और वहां का RFID स्कैनर खराब हो तो क्या होगा। क्या आपको कैश में टोल चुकाना होगा। आइए सुलझाते हैं इस गुत्थी को...

टोल प्लाजा पर फ्री में गुजर सकेंगे वाहन

NHAI के मुताबिक अगर किसी टोल पर RFID स्कैनर में कोई खराबी है और फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए वाहन चालक को कोई कोई पैसा नहीं चुकाना होगा और उसे फ्री में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए टोल प्लाजा को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें टोल पर बोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है, जिससे जागरुकता फैलाई जा सके।

क्या कहता है नियम

अगर आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं और RFID स्कैनर मशीन में खराबी है, और वह गाड़ी में फास्टैग को स्कैन नहीं कर पाता है तो और टोल प्लाजा का गेट नहीं खुलता है, तो नेशनल हाईवे फी रूल्स के मुताबिक टोल प्लाजा संचालक बिना टोल के ही जाने देगा। साथ ही वह मैनुअल तरीके जीरो फीस की रसीद भी काटेंगे, ताकि उस गाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। वहीं, अगर आपकी गाड़ी पर Fastag नहीं लगा है और आप टोल प्लाजा पर Fastag लेन से निकलना चाह रहें, तो आपको दोगुनी राशि चुकानी होगी। हालांकि, टोल प्लाजा पर एक लाइन बिना ईटी वाहनों के लिए भी होगा और इससे सामान्य टैक्स वसूला जाएगा।

एक दिसंबर से Fastag अनिवार्य

देश भर में एक दिसंबर से चार पहिया वाहनों पर Fastag अनिवार्य किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि आम जनता को जाम से निजात मिल सके। वहीं, एनएचआई के अनुसार अगर कोई ओवरलोड ट्रक टोल प्लाजा से गुजर रहा है, तो Fastag के जरिए ओवरलोड की राशि कट जाएगी।

यह होगा जुर्माने का नियम

एनएचएआई के मुताबिक, अगर किसी वाणिज्य वाहन पर 20 फीसदी तक ओवरलोड है, तो वाहन मालिक से दोगुना 20 से 40 फीसदी ओवरलोड पर चार गुना, 40 से 60 फीसदी ओवरलोड पर छह गुना, 60 से 80 फीसदी पर आठ गुना और 80 से 100 फीसदी ओवरलोड पर दस गुना तक का जुर्माने वसूला जाएगा। इसके लिए टोल पर वजन तोलने की मशीने जैसे उपकरण लगाए जा रहे हैं, तो ट्रक के वजन का आंकलन करके टोल राशि ऑटोमैटिक ही काट लेंगे।

Fastag का रंग निर्धारित

अधिकारियों के मुताबिक कार, जीप वैन के लिए नीले रंग का फास्ट टैग निर्धारित किया गया है। हल्के वाणिज्य वाहनों के लिए लाल व पीला रंग, बस के लिए हरा व पीला रंग, मिनी बस के लिए संतरी रंग निर्धारित किया गया है।

ट्र- क को उनकी क्षमता के अनुसार मिलेगा रंग

ट्रक को उनकी क्षमता के अनुसार रंग दिया गया है। 12 से 16 हजार किलो वजन वाले ट्रक को हरा रंग, 14,200 से 25 हजार किलो के ट्रक को पीला रंग, 25 से 54 हजार किलो के वजनी ट्रक को गुलाबी तथा 54,200 किलो से अधिक वजन के ट्रक को आसमानी रंग दिया गया है। जेसीबी व अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीन के लिए ग्रे रंग का फास्ट टैग निर्धारित हुआ है।

राजस्थान के बाड़मेर में प्रतिदिन 1.75 Crude Oil बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन

जयपुर। Crude Oil राजस्थान के रेतीले धोरों के नीचे एक बार कच्चे तेल के रूप में काला सोना निकलेगा। बाड़मेर के रेतीले धोरों में निकल रहे कच्चे तेल ने जहां प्रदेश की तकदीर बदलने का काम किया, वहीं अब बीकानेर जिले के सियासर ब्लॉक में तेल और गैस की खोज का काम शुरू किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल लिमिटेड ने करीब डेढ़ हजार ग्राउंड लाइन किलोमीटर में टू-डी सिस्मिक सर्वे का काम शुरू किया है। यह काम करीब एक साल में पूरा होने की उम्मीद है। ऑयल इंडिया जैसलमेर के साउथ बाधेवाला ब्लॉक में भी तेज की खोज का काम अगले कुछ दिनों में शुरू करेगी। बीकानेर के सियासर ब्लॉक और जैसलमेर के बाधेवाला ब्लॉक में कच्चे तेल की खोज के लिए कंपनी ने सरकार के साथ पिछले साल रेवेन्यू शेयरिंग अनुबंध किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कंपनी को तीन साल के लिए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया था। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने करीब दो साल पहले ऑन एरिया लाइसेंस पॉलिसी शुरू की थी। इसके तहत ऑयल इंडिया को देश के 21 बॉक्स में तेल और गैस की खोज का लाइसेंस दिया गया है। इनमें तीन ब्लॉक्स राजस्थान के है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एनजीटी ने दोषी माना

पानीपत रिफाइनरी पर 659 करोड़ जुर्माने की सिफारिश

पानीपत। एजेंसी

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्पेशल जॉइंट एक्शन कमिटी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत स्थित दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर 659 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। जुर्माने की राशि का प्रयोग रिफाइनरी क्षेत्र में स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। टिब्यूनल ने रिफाइनरी में वायु और जल प्रदूषण फैलाने के मामले की जांच के लिए स्पेशल जॉइंट एक्शन कमिटी का गठन किया था। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने पानीपत रिफाइनरी पर 17.31 करोड़ रुपये का जुर्माना किया था।

आरोपों से इनकार किया

पानीपत देश का 11 वां और हरियाणा का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला है। प्रदूषण फैलाने के लिए पानीपत रिफाइनरी पर कई बार अंगुली उठी, लेकिन हर बार रिफानइरी प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया। हालांकि पानीपत रिफाइनरी ने वायु व जल प्रदूषण से निपटने के लिए कभी जमीनी काम नहीं किया, जिससे प्रदूषण बढ़ता गया।

बढ़ता गया प्रदूषण

प्रदूषण से रिफाइनरी के आसपास स्थित गांवों न्यू बोहली, सिंहपुरा, सिठाना, ददलाना, रेर कलां, बाल जटान में रहने वाले नागरिकों की सेहत पर बुरा असर पड़ा। प्रदूषण का दुष्प्रभाव इंसानों के साथ मवेशियों और फसलों पर भी हुआ। ग्रामीणों ने रिफाइनरी प्रशासन से प्रदूषण को खत्म करने के लिए सशक्त कदम उठाने की गुहार लगाई, लेकिन रिफाइनरी प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता नहीं लिया ।

प्रशासन ने 2018 में की एनजीटी में शिकायत

रिफाइनरी प्रशासन से कई बार शिकायत करने और वहां से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर गांव सिठाना के सरपंच सत्यपाल ने प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ 2018 में नैशनल ग्रीन टिब्यूनल में शिकायत की। इस पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिफाइनरी की कार्यप्रणाली की जांच के लिए पानीपत के डीसी की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया। कमिटी की लंबे समय से चल रही जांच में पानीपत रिफाइनरी वायु और जल प्रदूषण फैलाने की दोषी पाई गई। तब कमिटी की रिपोर्ट पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पानीपत रिफाइनरी पर 17.31 करोड़ का जुर्माना किया था। पानीपत रिफाइनरी प्रशासन को आईओसीएल के उच्च अधिकारियों ने कड़ी फटकार लगाई थी।

पेट्रोल पंप नीति

कंपनियों को लगाने होंगे कम से कम 100 पेट्रोल पंप, 5 प्रतिशत दूरदराज इलाकों में हों

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने ईंधन क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति जारी की है। इसके तहत, ईंधन की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में उतरने वाली कंपनियों को देशभर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे और उनमें से पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप दूरदराज इलाकों में होने चाहिए। सरकार ने पिछले महीने ही कंपनियों के लिए पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में ढील दी थी। सरकार ने गैर- पेट्रोलियम कंपनियों को इस क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी है।

नई नीति के मुताबिक, देश में पेट्रोल पंप का लाइसेंस पाने के संशोधित प्रावधानों के तहत संबंधित कंपनी को न्यूनतम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे, जिनमें कम से कम पांच प्रतिशत दूरस्थ इलाके में होने चाहिए। एक राजपत्र अधिसूचना में पेट्रोल पंप लगाने के संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी गई है। इसके तहत, लाइसेंस पाने वाली कंपनी को पेट्रोल पंप का परिचालन शुरू होने के तीन साल के भीतर सीएनजी, बायो ईंधन, एलएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आदि जैसे वैकल्पिक माध्यमों में से किसी एक के विपणन की सुविधा भी लगानी होगी। इससे पहले पेट्रोल पंप का लाइसेंस पाने के लिए एक कंपनी को पेट्रोलियम क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत होती थी।

अधिसूचना के अनुसार, 'पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा विपणन का लाइसेंस पाने के लिए आवेदन करते समय कंपनी का न्यूनतम नेट वर्थ 250 करोड़ रुपये होना चाहिए।' सरकार ने पेट्रोल पंप पाने का आवेदन शुल्क 25 लाख रुपये तय किया है। अधिसूचना के अनुसार, लाइसेंस मिलने के पांच साल के भीतर कंपनी को देशभर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप खोलने होंगे, जिनमें कम से कम पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप दूरस्थ इलाकों में अवस्थित होने चाहिए। सरकार ने इससे पहले 2002 मे पेट्रोल पंप लाइसेंस आवंटन के प्रावधानों को संशोधित किया था। इस नीति की समीक्षा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद की गई है।सरकार के पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में गैर-पेट्रोलियम कंपनियों को प्रवेश देने की नीति से वैश्विक स्तर की कंपनियों जैसे की फ्रांस की टोटल एसए, सउदी अरब की आरामको, ब्रिटेन की बीपी पीएलसी और ट्राफिगुरा की विपणन कंपनी पमा एनर्जी को भारतीय बाजार में आने का रास्ता मिलेगा। इससे पहले फ्रांस की टोटल कंपनी अडाणी समूह के साथ मिलकर नवंबर 2018 में देश में 1,500 खुदरा पेट्रोल और डीजल पंप के लिए लाइसेंस का आवेदन कर चुकी है। बीपी ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पेट्रोल पंप खोलने के वास्ते भागीदारी की है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक औपचारिक तौर पर आवेदन नहीं किया है।पुमा एनर्जी ने खुदरा लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जबकि अरामको क्षेत्र में उतरने के लिए बातचीत कर रही है। फिलहाल, देश में वर्तमान में चल रहे 66,408 पेट्रोल पंपों में से ज्यादातर पंप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के ही हैं। इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यारा एनर्जी (पूर्व में एस्सार आयल) और रॉयल डच शेल निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भी पेट्रोल पंप चला रही हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत कम हे। रिलायंस के 1,400 पेट्रोल पंप हैं, जबकि उसकी सहयोगी बीपी ने भी 3,500 पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी शुरू नहीं किए हैं। शेल के 167 पेट्रोल पंप ही हैं।

सेंसेक्स 199 अंक चढ़कर 41020 के रिकॉर्ड स्तर पर, निफ्टी भी पहली बार 12100 पर बंद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

शेयर बाजार बुधवार को रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 199.31 अंक की बढ़त के साथ 41,020.61 पर बंद हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग 63 प्वाइंट ऊपर 12,100.70 पर हुई। ये दोनों इंडेक्स के रिकॉर्ड क्लोजिंग स्तर हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 254.46 अंक चढ़कर 41,075.76 का उच्च स्तर छुआ था। निफ्टी 77 प्वाइंट चढ़कर 12,114.90 तक पहुंचा था। दोनों इंडेक्स ने मिड-सेशन तक ज्यादातर बढ़त गंवा दी, लेकिन आखिरी घंटे में खरीदारी बढ़ गई। बैंकिंग, आईटी और ऑटो कंपनियों के शेयरों की मांग ज्यादा रही। विश्लेषकों के मुताबिक मजबूत विदेशी संकेतों से भारतीय बाजार में सेंटीमेंट बेहतर हुए। नवंबर वायदा एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग से भी सहारा मिला। सेंसेक्स के 30 में से 24 और निफ्टी के 50 में से 37 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एनएसई पर 11 में से 9 सेक्टर इंडेक्स फायदे में रहे। पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.77% तेजी आई। दूसरी ओर रिएलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 0.65% नुकसान में रहा।

राजस्थान के बाड़मेर में प्रतिदिन 1.75 बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केंद्र और राज्य दोनों की आय बढ़ी

उधर, बाड़मेर में प्रतिदिन 1.75 बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है। इससे राज्य सरकार को 15 और केंद्र सरकार को 32 करोड़ रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। बाड़मेर में हो रहे क्रूड ऑयल के उत्पादन से अब तक एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है। इसमें 65 लाख करोड़ केंद्र और करीब 35 लाख करोड़ राज्य सरकार को मिले हैं। बाड़मेर में तेल की खोज में जुटी केयर्न एनर्जी ने 6500 वर्ग किलोमीटर इलाके में 11 नए ब्लॉक्स की खोज शुरू कर दी है। राज्य के खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन का कहना है कि रेगिस्तानी इलाकों में तेल के उत्पादन से प्रदेश और देश को राजस्व मिलने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राज्य सरकार निरंतर तेल और गैस की खोज के लिए कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब जालौर में भी तेल के भंडार होने की जानकारी मिली है, वहां भी खोज का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।

बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत खुला

नई दिल्ली। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को मजबूती के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती के साथ 71.44 रुपये के स्तर पर खुला। वहीं, मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे की मजबूती के साथ 71.48 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 10 दिनों के रुपये का क्लोजिंग स्तर मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे की मजबूती के साथ 71.48 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की कमजोरी के साथ 71.72 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ 71.71 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे की मजबूती के साथ 71.76 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की कमजोरी के साथ 71.81 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती के साथ 71.70 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 71.84 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे की मजबूती के साथ 71.78 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की मजबूती के साथ 71.97 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 64 पैसे की कमजोरी के साथ 72.09 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। आजादी के समय रुपये का स्तर एक जमाना था जब अपना रुपया डॉलर को जबरदस्त टक्कर दिया करता था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो डॉलर और रुपये का दाम बराबर का था। मतलब एक डॉलर बराबर एक रुपया था। तब देश पर कोई कर्ज भी नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपये की साख भी लगातार कम होने लगी। 1975 तक आते-आते तो एक डॉलर की कीमत 8 रुपये हो गई और 1985 में डॉलर का भाव हो गया 12 रुपये। 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत ने उदारीकरण की राह पकड़ी और रुपया भी धड़ाम गिरने लगा। डिमांड सप्लाई तय करता है भाव करेंसी एक्सपर्ट के अनुसार रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इस पर असर पड़ता है। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, जिसमें वो लेन-देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अमरीकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है और ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं। पहली वजह है तेल के बढ़ते दाम रुपये के लगातार कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के बढ़ते दाम हैं। भारत कच्चे तेल के बड़े इंपोर्टर्स में एक है। भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसका बिल भी उसे डॉलर में चुकाना पड़ता है। दूसरी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में अक्सर जमकर बिकवाली करते हैं। जब ऐसा होता है तो रुपये पर दबाव बनता है और यह डॉलर के मुकाबले टूट जाता है। दूसरी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में अक्सर जमकर बिकवाली करते हैं। जब ऐसा होता है तो रुपये पर दबाव बनता है और यह डॉलर के मुकाबले टूट जाता है।

अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को जॉब वर्क पड़ेगा महंगा

ज्वैलरी, टेक्सटाइल जैसे मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स के 12% या 18% रेट पर सरकार की सफाई

नई दिल्ली। एजेंसी

ज्वैलरी, टेक्सटाइल, फर्नीचर, बिजली के उपकरण जैसे मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स के जॉब वर्क पर 12% जीएसटी रेट का फायदा तभी मिलेगा, जब सप्लायर रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड लोगों को दी गई सर्विस पर 18% रेट चार्ज होगा। इस बारे में जून और अक्टूबर में जारी सर्कुलर्स के बाद से इंडस्ट्री में काफी कन्फ्यूजन था और कई राज्यों में दोनों ही तरह के रेट चार्ज किए जा रहे थे।

जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के मुताबिक, पहली अक्टूबर से लागू नियमों के तहत ज्यादातर जॉब वर्क पर रेट 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था, लेकिन 9988 हेडिंग के तहत आने वाली जॉब वर्क सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के कुछ क्लॉज को लेकर दुविधा थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (CBIC) की ओर से जारी क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि 12% जीएसटी रेट किसी अन्य रजिस्टर्ड व्यक्ति के स्वामित्व वाली वस्तुओं की प्रोसेसिंग या ट्रीटमेंट पर चार्ज होगा, जबकि 18% रेट रजिस्टर्ड व्यक्तियों के अलावा अन्य सप्लायर्स के फिजिकल इनपुट्स (गुड्स) पर दी गई सर्विसेज के लिए है। बोर्ड ने कहा है कि 9988 हेडिंग के तहत आइटम (id) और (iv) के अंतर को साफ किया जा चुका है। पहले वर्ग में रजिस्टर्ड सप्लायर्स के इनपुट आते हैं, जबकि दूसरे में उनके अलावा सभी यानी अनरजिस्टर्ड सप्लायर आते हैं। गौरतलब है कि 9988 हेडिंग के तहत न्यूजपेपर की प्रिंटिंग, टेक्सटाइल यार्न, हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग, सोने के गहनों की मेकिंग, डिजाइनिंग, रत्न जड़ने का काम, किताब और पत्रिकाओं की छपाई, लेदर की प्रोसेसिंग, बिजली के उपकरणों आदि की प्रोसेसिंग आती है। जीएसटी एक्ट के तहत जॉब वर्क के लिए माल भेजने वाले इनपुट ओनर्स को प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कहा गया है और जॉब वर्कर के यहां माल भेजने से लेकर प्रोसेस होकर आने तक की टाइमलाइन तय है। इसमें कैपिटल गुड्स के लिए तीन साल और इनपुट के लिए एक साल का समय तय किया गया है। अगर इस अवधि के भीतर माल लौटकर प्रिंसिपल सप्लायर के पास नहीं आता है तो वह सर्विस जॉब वर्क नहीं मानी जाएगी, बल्कि गुड्स सप्लाई या बिक्री के रूप में ट्रीट की जाएगी। इसके लिए हर तिमाही प्रिंसिपल सप्लायर को एक खास रिटर्न (ITC-04) भरने की अनिवार्यता है। हालांकि जीएसटी लागू होने के दो साल बाद भी यह रिटर्न नाम मात्र ही फाइल हुआ था। इसे पिछले दिनों सरकार ने पहले साल के लिए स्वैच्छिक घोषित कर दिया था। इंडस्ट्री का कहना है कि जीएसटी काउंसिल का फैसला आने से पहले तक 18% रेट को लेकर काफी उथल-पुथल थी और कंपनियां सप्लाई पर टैक्स के बजाय प्रोसेसिंग पर टैक्स की लागत बढ़ने का हवाला दे रही थीं।

CBIC का स्पष्टीकरण

- 12% जीएसटी रेट किसी अन्य रजिस्टर्ड व्यक्ति के स्वामित्व वाली वस्तुओं की प्रोसेसिंग या ट्रीटमेंट पर चार्ज होगा
- 18% रेट रजिस्टर्ड व्यक्तियों के अलावा अन्य सप्लायर्स के फिजिकल इनपुट्स (गुड्स) पर दी गई सर्विसेज के लिए है

गूगल माई बिजनेस से आसानी से ऑनलाइन स्टोर खोल सकेंगे दुकानदार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

छोटे और मझोले कारोबारियों को आसानी से ऑनलाइन स्टोर खोलने की सुविधा देने के लिए गूगल 'माई बिजनेस' फीचर पेश करने जा रही है। यह कंपनी की गूगल शॉपिंग सेवा के तहत विकसित की गयी है। गूगल शॉपिंग के उपाध्यक्ष (उत्पाद प्रबंधन) सुरोजित चटर्जी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि कारोबारियों के खरीदारों से जुड़ने के लिए कंपनी अब नए फीचर 'गूगल माई बिजनेस' (जीएमबी) को पेश कर रही है। इसके तहत कोई भी खुदरा विक्रेता अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकेगा और ऑनलाइन सामान खोजने वाले लाखों खरीदारों से जुड़ सकेगा। इस सेवा के तहत जब भी कोई दुकानदार अपनी दुकान में मौजूद सामान की फोटो पोस्ट करेगा तो वह उत्पाद अपने आप गूगल शॉपिंग के सर्च में उत्पाद सूची के तौर पर दिखने लगेगा। इसके माध्यम से गूगल 20,000 से ज्यादा स्थानीय दुकानदारों को जीएमबी मंच पर ला चुकी है। यह फीचर उपलब्ध बनाया जा रहा है और भारतीय खरीदारों को अगले साल की शुरुआत में इसकी सेवा उपलब्ध होने लगेगी। गूगल शॉपिंग को पिछले साल दिसंबर में भारतीय बाजार में पेश किया गया था। इसमें ग्राहकों को किसी उत्पाद के लिए सर्च करने पर उस उत्पाद से जुड़े विभिन्न ऑफर, उत्पाद और दुकानों पर उपलब्धता की जानकारी आसानी से मिल जाती है। कंपनी ने कहा कि भारत गूगल शॉपिंग फीचर का उपयोग करने वाले प्रमुख देशों में से एक बन गया है। अधिक ग्राहकों से जुड़ने के लिए उसकी इस सेवा का उपयोग लघु और मध्यम उद्योग जमकर कर रहे हैं। चटर्जी ने कहा, "पिछले साल गूगल शॉपिंग को भारतीय बाजार में उतारने के बाद से हमने तेज गति से बढ़त दर्ज की है। भारतीय ग्राहक अक्सर हमारे मंच पर खरीदारी करने के अनुभव से जुड़ते हैं और यह उनके किसी अन्य बाजार (ई-वाणिज्य) मंच बिताए गए वक्त की तुलना में अधिक है।" चटर्जी ने कहा कि अब गूगल शॉपिंग मंच पर 20 करोड़ से अधिक ऑफर उपलब्ध हैं। हमारी साइट पर खरीदारी के लिए किए जाने वाले सर्च में बढ़त दर्ज की गयी है। लघु एवं मध्यम उदयोग कारोबार की वेबसाइटों पर सूचीबद्ध उत्पादों तक पहुंच के मामले में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गयी है।

GST प्राधिकरण ने 140 करोड़ रुपये की कर धोखाधड़ी का पता लगाया

नई दिल्ली। जीएसटी प्राधिकरण ने कर चोरी करने वाले गिरोह का पता लगाया है। प्राधिकरण ने धोखाधड़ी कर सरकार को करीब 140 करोड़ रुपये का चूना लगाने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (ऍघ्ध) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय जीएसटी दिल्ली उत्तरी आयुक्त कार्यालय ने कर चोरी करने वाले गिरोह का पता लगाया है। यह गिरोह बिना बिल के वस्तुओं की आपूर्ति में लगा था। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।आरोपी 10 फर्जी कंपनियों का परिचालन कर रहा था। उसने धन को इधर-उधर किया और धोखाधड़ी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रथम दृष्टि में कुल 1,040 करोड़ रुपये राशि के बिलों को दिखाकर 140 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी की गई।

GST दायरे पर स्पष्ट नहीं गाइडलाइन्स, BPO इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहा इनपुट टैक्स रिफंड

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय बीपीओ (बिजनस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग) इंडस्टी असमंजस में है। एक्सपोर्ट इकाइयों को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट वर्गीकरण न होने को लेकर इंडस्ट्री इनपुट टैक्स रिफंड को लेकर परेशान है। टैक्स अधिकारी बीपीओ इकाइयों को सही गाइडलाइन्स न मिलने की वजह से फिलहाल रिफंड करने में कोताही बरत रहे हैं। सितंबर में जीएसटी काउंसिल के सामने एक्सपोर्ट और इंटरमीडियरी इकाइयों को लेकर तस्वीर साफ करने का सुझाव रखा गया था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। सुझाव था कि बीपीओ को निर्यात का दर्जा देकर 18 पर्सेंट उएऊ के दायरे से बाहर निकाला जाए। इसपर फिर सिरे से चर्चा शुरू हो गई है, सरकार ने नया सर्कुलर ड्राफ्ट किया है और यह मुद्दा फिर जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'स्पष्ट रूप से यह बताए जाने की जरूरत है कि कौन-सी एंटिटी इंटरमीडियरी है और कौन-सी नहीं।' महाराष्ट्र की अपीलेट अथॉरिटी फॉर अडवांस रूलिंग (AAAR) ने फरवरी में कहा था कि बैक-ऑफिस सपॉर्ट को सर्विस एक्सपोर्ट का दर्जा नहीं दिया जाता। इसमें अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और उनके ग्राहकों को गुड्स और सर्विसेज मुहैया कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये सेवाएं इंटरमीडियरी सर्विसेज का हिस्सा हैं और इन पर उएऊ लागू होता है। आमतौर पर निर्यातकों को टैक्स रिफंड किया जाता है क्योंकि इन्हें विदेश में कन्ज्यूम किया जाता है। पुराने टैक्स रूल्स में भी बैक-ऑफिस सर्विस को यह स्टेटस हासिल था।

फूड एग्रीगेटर्स और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ छूट का झगड़ा नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों और रेस्टोरेंट्स के बीच गतिरोध का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि फूड एग्रीगेटर्स भारी छूट देने के अलावा उन पर कई 'मुश्किल शर्तें' लाद रहे हैं। जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियां भी अपनी गलती मानकर मोटे डिस्काउंट के साथ अन्य ऑफर्स को वाजिब स्तर पर लाने को राजी हो गई हैं, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ईकॉमर्स दिग्गज एमेजॉन भी फूड डिलीवरी मार्केट में उतरने वाली है। इससे ग्राहक बढ़ाने के लिए भारी छूट का खेल फिर से शुरू हो सकता है।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को हर महीने 500 से ज्यादा शहरों से करीब 8 करोड़ ऑर्डर मिलते हैं। यह कारोबार तकरीबन पांच साल पहले शुरू हुआ था। इस सिस्टम में फूड एग्रीगेटर्स तय कमीशन के बदले रेस्टोरेंट को ऑर्डर दिलवाते थे। रेस्टोरेंट को सिर्फ खाना बनाकर पैक करना होता था। उन्हें नियमित ग्राहकों के अलावा अतिरिक्त कमाई तो मिलती ही थी, उनके प्लेटफॉर्म का प्रचार भी होता था। लिहाजा, रेस्टोरेंट्स ने इस मॉडल को धड़ल्ले से अपनाया। हालांकि, जब स्विगी, जोमैटो, फूडपांडा और उबरईट्स ने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए भारी छूट और मनमानी शर्तें लादने का खेल शुरू किया तो रेस्टोरेंट्स को अहसास हुआ कि यह उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है।

फूड एग्रीगेटर्स चाहते हैं कि रेस्टोरेंट्स छूट के बड़े हिस्से का बोझ खुद उठाएं। वे प्राइम या गोल्ड मेंबर की अतिरिक्त डिश या ड्रिंक का बोझ भी रेस्टोरेंट्स के सिर डालना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स के लिए यह घाटे का सौदा है क्योंकि फूड डिलीवरी कंपनियां मेंबरशिप से होने वाली आमदनी उनसे साझा नहीं करतीं। वहीं, रेस्टोरेंट्स किराया बढ़ने, कारोबारी सुस्ती और बाहर जाकर खाने वाले बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपने मुनाफे से समझौता नहीं करना चाहते। एग्रीगेटर्स यह भी चाहते हैं कि रेस्टोरेंट्स और कम समय में खाना तैयार करें। रेस्टोरेंट्स की शिकायत है कि कई ऐसे आइटम हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। लिहाजा, एग्रीगेटर्स का यह दबाव ज्यादती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर रेस्टोरेंट्स को एग्रीगेटर्स से इतनी शिकायतें हैं तो वे उनका प्लेटफॉर्म छोड़ क्यों नहीं देते? कई रेस्टोरेंट्स जोमैटो और स्विगी के प्लेटफॉर्म से हट चुके हैं।

हालांकि, यह समस्या अब डिस्काउंट और शर्तों से आगे बढ़कर आस्तिव की लड़ाई बन गई है। दरअसल, फूड डिलीवरी कंपनियों ने रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर तो खूब दिलाए, लेकिन साथ में ग्राहकों की खानपान की आदत को भी बदला। अब लोग खाना मंगाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इससे पैसा और समय दोनों बचता है। फूड एग्रीगेटर्स को रेस्टोरेंट्स के साथ विवाद का पहले से अंदेशा था। लिहाजा, उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोलना भी शुरू कर दिया है, जहां सिर्फ डिलीवरी के लिए खाना बनाया जाता है। स्विगी ने क्लाउड किचन लॉन्च किया है, जिसमें वह थर्ड पार्टी रेस्टोरेंट्स को खाना बनाने की सहूलियत देती है। उसके पास निजी फूड ब्रांड 'बाउल कंपनी' भी है। इन सबके चलते रेस्टोरेंट्स को डर है कि फूड एग्रीगेटर्स उनका मार्केट और कस्टमर छीन लेंगे।

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ॅ) की फूड सर्विस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने वालों की संख्या 90 प्रतिशत और डिलीवरी सर्विस की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत थी। 1,800 से ज्यादा मेंबर रेस्टोरेंट्स वाली एसोसिएशन ॅ ने पिछले दिनों भारी डिस्काउंट के खिलाफ क्ष्थ्दुदलू अभियान चलाया, जिसके तहत एग्रीगेटर्स की डाइन-इन सर्विसेज को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। जोमैटो के फाउंडर दीपेंदर गोयल ने पिछले गुरुवार को ट्वीट किया था कि ॅ प्रेसिडेंट राहुल सिंह भी अपनी रेस्टोरेंट्स चैन बीयर कैफे में फूड डिलीवरी कंपनियों की डिस्काउंट स्कीम चलाते हैं। हालांकि, दोनों पक्षों ने बाद में मसले को सुलझा लिया। फूड एग्रीगेटर्स डिस्काउंट सहित अन्य ऑफर्स को वाजिब स्तर पर लाने को राजी हो गए।

एमेजॉन भी फूड डिलीवरी सेगमेंट में उतर रही है। वह अभी सिर्फ रेस्टोरेंट्स को जोड़ने की कोशिश में है। मौजूदा एग्रीगेटर्स जहां 16-17 प्रतिशत तक कमीशन लेते हैं, वहीं एमेजॉन सिर्फ 6-7 प्रतिशत लेकर ऑर्डर दिलाने का ऑफर दे रही है। इससे रेस्टोरेंट्स उसके पाले में जा सकते हैं। हालांकि, स्विगी भी शुरुआत में 4 प्रतिशत तक ही कमीशन लेती थी। एमेजॉन की एंट्री से इंडस्ट्री में कॉम्पिटीशन बढ़ेगा, जो फिलहाल स्विगी और जोमैटो जैसी दो बड़ी स्टार्टअप के बीच सिमट चुका था। इस प्रतिस्पर्धा से कीमतों की जंग फिर शुरू हो सकती है।

जल्द घट सकती हैं 80% दवाओं की कीमतें

ट्रेड मार्जिन 30% रखने के प्रस्ताव पर सहमति

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आने वाले समय में देशवासियों को महंगी दवाओं से राहत मिल सकती है। घरेलू दवा इंडस्ट्री और कारोबारियों ने प्राइस कंट्रोल से बाहर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक रखने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। इस कदम से देश में लगभग 80 फीसदी दवाओं की कीमतें घटेंगी। शुक्रवार को ड्रग प्राइस रेग्युलेटर, फार्मा लॉबी ग्रुप तथा उद्योग संगठनों के बीच हुई बैठक में प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है। बैठक में मौजूद सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ट्रेड मार्जन पर 30% की ऊपरी सीमा को अन्य प्रस्तावों जैसे प्राइस कंट्रोल वाली दवाओं सहित तमाम दवाओं पर फ्लैट 100% ट्रेड मार्जिन पर तवज्जो दी गई।

'चरणबद्ध तरीके से हो लागू'

इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (IDMA) के प्रेजिडेंट दीपनाथ रॉय चौधरी ने कहा, 'ट्रेड मार्जिन के रेशनलाइजेशन में हमें कोई परेशानी नहीं है। कैंसर रोग की दवाओं पर भी ट्रेड मार्जिन को 30% पर फिक्स किया गया है, वह भी ठीक है। अगर इसे अन्य उत्पादों पर भी लागू किया जाता है, तो इसे चरणबद्ध तरीकों से लागू किया जाना चाहिए।'

कंपनियां पहले से थीं सहमत

मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि तमाम भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय फार्मा लॉबी 30% की ऊपरी सीमा से सहमत थे। उन्होंने कहा, 'यह मार्जिन स्टॉकिस्टों के प्राइस के 43% मार्क-अप के समतुल्य है।'

बड़ी कंपनियों पर बड़ा असर

सरकार के इस कदम से जेनरिक डिविजंस के साथ बड़ी फार्मा कंपनियों जैसे सन फार्मा, सिप्ला तथा ल्यूपिन पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) में कटौती करनी पड़ेगी। मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन आरसी जुनेजा ने ट्रेड मार्जिन को 30% पर फिक्स करने के प्रस्ताव को उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा है कि इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।

'ज्यादा अंतर नहीं आएगा'

फिलिप कैपिटल के फार्मा एनालिस्ट सूर्य पात्रा ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर की दवाओं पर 30 फीसदी का ट्रेड मार्जिन पहले से चलन में है। इसमें रिटेलर का 20 फीसदी और होलसेलर का 10 फीसदी मार्जिन होता है। इसलिए नए प्रस्ताव के लागू होने के दवाओं की कीमतों में ज्यादा कमी नहीं आएगी। दवा कंपनियां जिस दाम पर स्टॉकिस्ट को माल बेचती है और जो दाम ग्राहक से वसूला जाता है, उसके अंतर को ट्रेड मार्जिन कहा जाता है।

आपूर्ति से एक घंटा पहले बिजली खरीदने की व्यवस्था एक अप्रैल से हो सकती है शुरू: सीईआरसी चेयरमैन

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पी के पुजारी ने बुधवार को कहा कि खरीद के साथ ही कम से कम समय में बिजली आपूर्ति शुरू करने की व्यवस्था अगले साल एक अप्रैल से शुरू हो सकती है। इसमें बिजली वितरण कंपनियां या निजी उपयोग के लिये बिजली संयंत्र चलानी वाली इकाइयों के ग्राहक आपूर्ति से महज एक घंटा पहले बिजली खरीद कर सकेंगे। फिलहाल बिजली बाजारों में अगले दिन की आपूर्ति के लिये एक दिन पहले (डीएएम) बिजली खरीद करनी होती है। इन बाजारों में दो घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कारोबार होता है।

इंडिया एनर्जी फोरम के 22वें इंडिया पावर फोरम के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत में पुजारी ने संवाददाताओं से कहा, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि वास्तविक समय पर आधारित बिजली बाजार एक अप्रैल 2020 से काम करने लगेगा। वास्तविक समय आधारित बिजली बाजार पर संबद्ध पक्षों के साथ नियमन रूपरेखा पर चर्चा पूरी हो चुकी है।"हालांकि, उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि सीईआरसी द्वारा नियमन की मंजूरी के बाद वास्तविक समय पर आधारित बिजली बाजार तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिये हमें प्रणाली बनानी है। साफ्टवेयर (कारोबार समाधान) तैयार करना होगा और लोगों को उसके बारे में शिक्षित करने की जरूरत होगी।"इसके अमल में आने के साथ बिजली वितरण कंपनियां समेत उपभोक्ता बेहतर तरीके से ऊर्जा आपूर्ति की योजना बना सकते हैं। वहीं बिजली उत्पादक कंपनियां अपना उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ा या घटा सकती हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित मसौदा नियमन के तहत एक दिन में आधे-आधे घंटे के 48 सत्र होंगे। इसका मतलब है कि बिजली का कारोबार 24 घंटे हो सकेगा। इसमें अगर उपभोक्ता दोपहर 1.30 से 2 बजे के सत्र में बिजली खरीदता है, तब बिजली आपूर्ति उसी दिन दोपहपर तीन बजे से की जा सकती है।इससे पहले, उन्होंने सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि नियामक ने बिजली क्षेत्र में कई नियमनों का प्रस्ताव किया है जो अगले साल एक अप्रैल से प्रभाव में आ सकता है। इसमें वास्तविक समय पर आधारित बिजली नियमन प्रमुख है।उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 साल में बिजली क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में काफी कुछ किया गया है लेकिन अभी काफी कुछ किये जाने की जरूरत है। सम्मेलन में टेरी के महानिदेशक अजय माथुर, इंडिया एनर्जी फोरम के अध्यक्ष अनिल राजदान समेत अन्य लोगों ने भी अपनी बातें रखी।

केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

FCI की अधिकृत पूंजी को 10000 करोड़ रुपये किया गया

नई दिल्ली। बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय खाद्य निगम (इण्ध्) की अधिकृत पूंजी को मौजूदा 3500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है।सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के इस निकाय में अतिरिक्त पूंजी डालने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके साथ ही एफसीआई अपने कर्ज और ब्याज लागत को भी कम कर सकेगा। इससे एफसीआई की उधारी में कमी के साथ एफसीआई की ब्याज लागत में कमी और खाद्य सब्सिडी में कम होगी।बैठक में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 12 महीने बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। इस फैसले से वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जूट इंडस्ट्री के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी अनाजों की 100 फीसद पैकेजिंग में जूट की बोरियों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। केन्द्रीय कैबिनेट ने अपने बैठक में सिक्किम माइनिंग कॉर्पोरेशन के बकाया 4 करोड़ से अधिक के कर्ज़ और ब्याज के पुनर्भुगतान की छूट की मंजूरी दी है।

भारत सरकार की खाद्य नीति को लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था। इसको बनाने का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का वितरण करना है।

रेलवे को 2018-19 में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री से हुई 139 करोड़ रुपये की आय: मंत्री

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रेलवे को 2018-19 में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से 139.20 करोड़ रुपये की आय हुई। बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से मौजूदा वित्त वर्ष में सितंबर महीने तक 78.50 करोड़ रुपये की आय हुई।गोयल ने कहा कि 2018-19 में स्टेशनों से विज्ञापनों एवं दुकानों से 230.47 करोड़ रुपये का राजस्व आया। बता दें कि भारतीय रेलवे को 10 सालों में कबाड़ (स्क्रैप) बेचकर 35,073 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। रेलवे ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में यह जानकारी साझा की। रेल मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2009-10 से वर्ष 2018-19 की अवधि के बीच विभिन्न तरह के कबाड़ बेचकर विभाग ने 35,073 करोड़ रुपये कमाए। इसमें कोच, वैगन्स और पटरी के कबाड़ शामिल हैं। बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा कबाड़ स्क्रैप 4,409 करोड़ रुपये का वर्ष 2011-12 में बेचा गया, जबकि स्क्रैप से सबसे कम आमदनी वर्ष 2016-17 में 2,718 करोड़ रुपये हुई।

नये मोटर कानून के बाद दुर्घटना से मौत में भारी कमी: सरकार

नयी दिल्ली। नए मोटर वाहन कानून के एक सितंबर से अमल में आने के बाद, चंडीगढ़ सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारी कमी आई है। सितंबर और अक्टूबर में ऐसे घातक हादसों में 75 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी है। यह जानकारी सोमवार को संसद को दी गयी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि सितंबर और अक्टूबर में चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में केवल दो व्यक्ति मारे गए, जबकि यह संख्या एक साल पहले की समान अवधि में आठ थी। इसी प्रकार पुडुचेरी में वर्ष 2018 के समान अवधि के दौरान हुए सड़क दुर्घटनाओं में मौत की तुलना में हादसे 31 प्रतिशत घटकर केवल नौ रह गई। उत्तराखंड में सितंबर और अक्टूबर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या 22 प्रतिशत घटकर 61 रह गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह संख्या 78 थी।

गडकरी ने कहा कि गुजरात में मृत्यु भी इन महीनों में घटकर 480 रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि के 557 मौतों के मुकाबले 14 प्रतिशत कम है। बिहार में इन दो महीनों में, वर्ष 2018 के इन दो महीनों में 459 मौतों की तुलना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान, मृत्यु दर 10.5 प्रतिशत घटकर 411 रह गई। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या 10 प्रतिशत घटकर 1,355 रह गई जो वर्ष 2018 की सितंबर से अक्टूबर की अवधि में 1,503 के मुकाबले मौतें हुईं। गडकरी ने कहा कि केरल में सड़क दुर्घटना से संबंधित मौतों में 2.1 प्रतिशत की कमी आई जबकि छत्तीसगढ़ में दुर्घटना से संबंधित मौतों में 4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

पिछले सप्ताह, सरकार ने संसद को सूचित किया था कि नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद से कुल 577.5 करोड़ रुपये की राशि वाले 38 लाख चालान जारी किए गए हैं।हालाँकि, यह कहा गया था कि 'चालान अदालतों के लिए संदर्भित किए जा रहे हैं इसलिए वास्तविक राजस्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14,13,996 चालान काटे गये, जबकि सबसे कम चालान गोवा में यानी 58 चालान ही काटे गये। सरकार ने हाल ही में कहा था कि उसे किसी भी राज्य के द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू नहीं करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, कुछ राज्यों ने अधिनियम के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार दंड की मात्रा में थोड़ी कमी की है। सख्त प्रावधानों और उच्च दंड राशि वाले कानून को एक सितंबर से देश में लागू किया गया था।

देश में कागज की खपत 2024-25 तक 2.4 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय कागज उद्योग का अनुमान है कि देश में कागज उद्योग औसतन सालाना 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकता है और इसके साथ अगले पांच साल में 2024-25 तक कागज की घरेलू खपत 2.4 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। कागज विनिर्माताओं के संघ इंडियन पेपर एंड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस समय कागज की खपत 1.5 करोड़ टन है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सेंचुरी पेपर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. पी. नारायण ने राजधानी में अगले सप्ताह आयोजित की जा रही कागज उद्योग की प्रदर्शनी पेपरएक्स2019 से पहले विज्ञप्ति में कहा, ''कागज उद्योग बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कुछ बड़ी कागज कंपनियां अपने किसी क्षेत्र, उत्पाद या श्रेणी विशेष की मांग को मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार

कर रही हैं।'' उन्होंने कहा, '' अभी देश में कागज की कुल खपत डेढ़ करोड़ टन है जिसके 2024-25 तक बढ़कर 2.4 करोड़ टन होने का अनुमान है।'' नारायण ने कहा कि इस उद्योग की सालाना वृद्धि करीब 12 प्रतिशत रहने की उम्मीद हैं पेपरएक्स, कागज उद्योग से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। इस साल यह 3-6 दिसंबर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की जा रही है। विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। कागज उद्योग क्षेत्र के वैश्विक समूह एशियाहाइव ग्रुप के क्षेत्रीय निदेशक गार्डन पेनी ने कहा, ' भारत को पेपरएक्स उद्योग प्रदर्शनी के आयोजन पर वास्तव में गर्व होना चाहिए। यह उद्यमियों को इस उद्योग के ताजा रुझानों और प्रौद्योगिकी को एक साथ देखने समझने तथा नए पुराने उद्यमियों को आपस में मिलने का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराती है।''

संघ ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस प्रदर्शनी में 28 देशों के 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रदर्शनी में करीब 30,000 कारोबारी आगंतुकों के आने का अनुमान है। कागज उत्पादन से जुड़े देशभर के 1,100 से अधिक लघु उद्योग (एमएसएमई) पहली बार इस प्रदर्शनी में शामिल होंगे। नारायण ने कहा, ''मेरा मानना है कि देश में इस उद्योग के अंदर विलय और एकीकरण के रुझान बढ़ेंगे। हमें अधिक कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण देखने को मिल सकते हैं। चूंकि इस उद्योग में श्रमबल की आवश्यकता होती है, इसलिए उद्योग के विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेगा।'' वर्तमान में देश में 462 कागज मिलें हैं। यह हर साल करीब तीन करोड़ टन कागत का उत्पादन करती हैं। पिछले तीन साल में देश का कागज निर्यात 6.6 लाख टन से बढ़कर 15 लाख टन हो गया है।

एफएसएसएआई ने पैकेट बंद दुग्ध उत्पादों से जीएसटी हटाने की वकालत की

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य नियामक एफएसएसएआई पैकेज्ड दुग्ध उत्पादों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने के लिए जीएसटी परिषद को पत्र लिखेगा ताकि ऐसे उत्पादों की बिक्री को बढ़ाया जा सके। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि हाल में खुदरा बाजारों में बिकने वाले दुग्ध उत्पादों के नमूनों का परीक्षण किया गया था। इसमें गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़ी कमियां पाई गई थीं। जिसके बाद से पैकेट बंद दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में दुग्ध उत्पादों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर दूध एवं उससे बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्ययोजना पेश करते हुए अग्रवाल ने कहा कि एफएसएसएआई ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों को परीक्षण से जुड़े उपकरण दिए हैं। खाद्य नियामक ने देशभर के 25 लाख विक्रेताओं में से एक लाख दूध विक्रेताओं को सत्यापित करने के लिए एक योजना शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दुग्ध विक्रेताओं का पंजीकरण पहले से अनिवार्य है लेकिन करीब पांच प्रतिशत विक्रेताओं ने इसका अनुपालन किया है। अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया , ' दूध एवं दुग्ध उत्पाद सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी कमियों से निपटने के लिए हमने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। हमने शुरुआत में एक लाख विक्रेताओं का सत्यापित करने का लक्ष्य रखा है। ' ' सत्यापित दुग्ध विक्रेता योजना ' के तहत , दूध विक्रेता खुद से पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और उन्हें फोटो - पहचान पत्र और लैक्टोमीटर दिया जाएगा।

'आधार' को सुरक्षित मानते हैं 90% भारतीय: सर्वेक्षण

नई दिल्ली। एजेंसी

बायोमेट्रिक आधारित पहचान 'आधार' को 90 प्रतिशत भारतीय सुरक्षित मानते हैं। हालांकि, लोगों का मानना है कि आधार को अद्यतन (अपडेट) कराना सबसे मुश्किल काम है। सामाजिक मसलों पर परामर्श देने वाले गैर-सरकारी संगठन डालबर्ग की एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात कही गई है। संगठन की रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ आधार-2019' के सह-लेखक गौरव गुप्ता ने सोमवार को सर्वेक्षण के नतीजों को सामने रखते हुए कहा कि आधार को 90 प्रतिशत लोग सुरक्षित मानते हैं तथा 61 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इसके कारण उन्हें मिलने वाला लाभ कोई अन्य नहीं उठा पाता है।

92%लोग आधार से संतुष्ट

सर्वेक्षण में शामिल 92 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे आधार से संतुष्ट हैं। डालबर्ग ने यह सर्वेक्षण निवेश फर्म ओमिदयार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 95 प्रतिशत व्यस्कों तथा 75 प्रतिशत बच्चों के पास आधार है। उन्होंने कहा कि अभी करीब 2.8 करोड़ व्यस्कों के पास आधार नहीं है। कुल 10.2 करोड़ लोगों के पास आधार नहीं होने का अनुमान है।

असम, मेघालय में अधिकतर के पास आधार नहीं

असम और मेघालय में अधिकतर लोगों के पास आधार नहीं है। असम में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत और मेघालय में 61 प्रतिशत है। देश के 30 प्रतिशत ट्रांसजेंडर तथा 27 प्रतिशत आवासहीन लोगों के पास अभी तक आधार नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने आधार को अपडेट कराना सबसे मुश्किल काम बताया है। आधार को अपडेट करने की कोशिश कराने वाले प्रत्येक पांच लोगों में एक को निराशा मिली है।

4% ने मानी आधार में त्रुटि की बात

आधार में दर्ज जानकारियों के बारे में महज चार प्रतिशत ही लोग हैं, जिन्होंने इसमें त्रुटि की बात स्वीकार की है। गुप्ता ने कहा कि करीब 80 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इसके कारण राशन और पेंशन जैसी सुविधाएं सरल हुई हैं। चालीस प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें आधार के कारण एक ही दिन में मोबाइल सिम कार्ड पाने की सहूलियत मिली है। करीब आठ प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए आधार उनका पहला पहचान पत्र रहा है।

आधार नहीं होने से स्कूलों में दाखिला नहीं मिला

सर्वेक्षण में शामिल करीब आधे लोगों ने माना कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिकतर कंपनियां मोबाइल सिम के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए और स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिए केवल आधार को ही पहचान के तौर पर स्वीकार करते हैं। आधार नहीं होने की वजह से 6 से 14 वर्ष की आयु के करीब 0.5 प्रतिशत बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिला है।

72% लोगों ने आधार को सुविधाजनक माना

पहचान के तौर पर आधार को हर जगह स्वीकार किए जाने को 72 प्रतिशत लोगों ने सुविधाजनक माना है, जबकि इनमें से करीब आधे लोगों ने बहुत सारी सेवाओं के साथ इसे जोड़ने पर चिंता भी व्यक्त की। आधार के साथ कई नए फीचर जैसे कि एमआधार, क्यूआर कोड, वर्चुअल आधार और मास्क्ड आधार भी शुरू की गई हैं, लेकिन 77 प्रतिशत लोगों ने इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया है।

साइबर सुरक्षा पर उन्नत कार्यक्रम शुरू करेगा आईआईटी कानपुर

हैदराबाद। एजेंसी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , कानपुर (आईआईटी - कानपुर) ने साइबर सुरक्षा एवं साइबर रक्षा पर एक उन्नत ' सर्टिफिकेट प्रोग्राम' शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। इसके लिए उसने टैलेंटस्प्रिंट के साथ साझेदारी की है। आईआईटी कानपुर के कार्यक्रम निदेशक और कंप्यूटर साइंस के प्राध्यापक मनिंद्र अग्रवाल ने यहां मीडिया से कहा , ' यह कार्यक्रम साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में हो रहे नए - नए बदलावों को जानने के इच्छुक पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। इसका पहला ई - सत्र 2020 के शुरू में चालू होगा। उन्होंने कहा , ' मोबाइल , इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के तेजी से बढ़ते उपयोग से सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए इन खतरों से निपटने की जरूरत बढ़ती जा रही है। '

'मैं' से मुक्त कराते हैं सच्चे गुरु

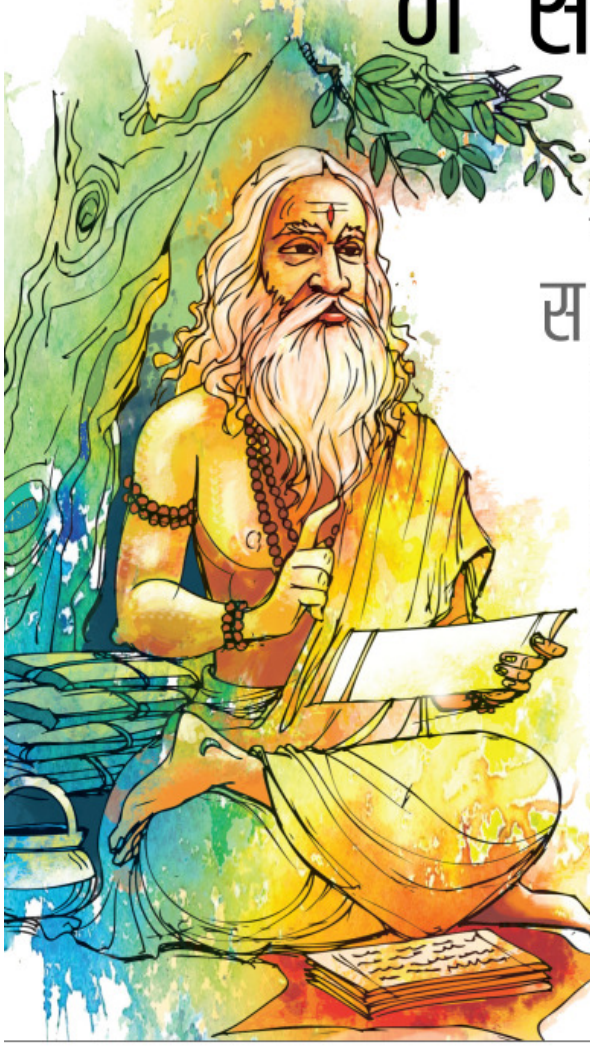

सद्गुरु व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन यह मार्ग उन्हीं को दिखाई दे सकता है, जिनका हृदय कलुषरहित हो, जो अनासक्त हो। जो सद्गुरु से मिलने के बाद भी अपने 'मैं' को साथ रखते हैं, वे अपने और परमात्मा के बीच एक दीवार बना लेते हैं।

अध्यात्म

आनन्दमूर्ति गुरुमां

सद्गुरु की महिमा में यह कहा जाता है कि उनके एक दर्शन मात्र से व्यक्ति में सारे आध्यात्मिक गुण जग जाते हैं। हालांकि ये ऐसे व्यक्ति में जगते हैं, जिसका मन शुद्ध और दोषरहित हो। उस व्यक्ति का मन कितना सुंदर होगा, जो मात्र सद्गुरु के दर्शन से गुरु की प्रज्ञा, गुरु की आभा तथा गुरु का वैराग्य प्राप्त कर लेता हो। ये सभी गुण सहजतापूर्वक उस खोजी तक पहुंच जाते हैं, जिसका चित्त शुद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति सद्गुरु से मिलते समय अपने चित्त और हृदय के किवाड़ पूर्णतया खोलकर रखता है।

अज्ञान, अहंकार, ईर्ष्या की जो इतनी मोटी दीवारें आपने निर्मित कर रखी हैं, इनको हटा दें। सद्गुरु और अपने मन में स्वयं ही दीवार निर्मित करने की वजह से आप सद्गुरु मिलने के बावजूद भी भटकते रहते हो। सद्गुरु मिलने के बाद भी आपका मन बेचैन और अशांत रहता है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि आपने अभी सद्गुरु के साथ आंतरिक संबंध स्थापित ही नहीं किया है।

सद्गुरु का अर्थ है ज्ञान और विवेक। जिसके पास विवेक है, उसका मन कभी भी संसार से आसक्त नहीं हो सकता। उसका मन हर तरह की इच्छाओं और घृणाओं से मुक्त रहता है। वह लोगों में पक्षपात नहीं करता। आप अगर पक्षपात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में इन आध्यात्मिक गुणों का अभाव है। फिर आपकी बुद्धि में विवेक का प्रकाश भी कैसे हो सकता है?

आपके संसार का आरंभ आप ही से होता है। 'मैं हूं' इस अज्ञान के साथ ही संसार का आरंभ होता है। संसार 'मैं' की दृष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दिन के 24 घंटे में आप कितनी बार 'मैं' और 'मेरा' कहते हो? जिस क्षण व्यक्ति इस 'मैं' से मुक्त होता है, वही क्षण मोक्ष का क्षण होता है। एक सद्गुरु ही जीवन में आई इस 'मैं' और 'मेरे' की समस्या का समाधान देते हैं। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जब आपका मन तनाव से भ्रमित हो जाता है और कोई हल नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों में सद्गुरु ही तनावग्रस्त चित्त को सहारा देते हैं।

जिसका चित्त सद्गुरु से जुड़ा है, वही मुसीबत में सद्गुरु तक पहुंच पाता है। जो कभी सद्गुरु से जुड़ा ही नहीं, वह विपत्ति के समय केवल रोता रहता है। जिनसे सहारा मिल सके, उन सद्गुरु को पुकारना उसे आता ही नहीं। यह कैसी विचित्र माया है कि आदमी ऐसी परिस्थितियों के चंगुल में फंस जाता है और उसे अपने गुरु से आंतरिक मदद लेने का ख्याल ही नहीं आता। जिसने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया हो, केवल वही अपने आपको सहारा देकर प्रभु की शरण में ला सकता है। जब हमारा चित्त संसाररूपी वन में भ्रमित हो जाता है, तब सद्गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब सद्गुरु ही हमें राह दिखा सकते हैं। सद्गुरु ही हमारे कल्याण की चिंता करते हैं, जो हमारा हाथ थाम कर तूफानी सागर में प्रेमपूर्वक हमारी पतवार संभालते हैं।

> सद्गुरु का अर्थ है ज्ञान और विवेक। जिसके पास विवेक है, उसका मन कभी भी संसार से आसक्त नहीं हो सकता। उसका मन हर तरह की इच्छाओं और घृणाओं से मुक्त रहता है।

गुरु के दिखाए मार्ग पर निश्चयपूर्वक चलते जाओ, तो वह शुभ घड़ी आपके जीवन में भी अवश्य आएगी, जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होंगे। घर बनाना, पैसे कमाना यही केवल आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन प्राप्त होने के बावजूद अगर आप अपना मन जीतने में समर्थ नहीं हो पाते हो, तो आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। मन का मालिक बनने की कला प्राप्त करना, यह कार्य केवल साधुओं तक ही सीमित नहीं है। यह तो संपूर्ण मानव जाति का लक्ष्य होना चाहिए।

सभी समस्याओं की जड़ है आपका मन। अनियंत्रित मन से बड़ा शत्रु और कोई नहीं। यदि संबुद्ध गुरु मिलने के बावजूद आप ईर्ष्या, क्रोध और छल से भरे अज्ञानी बने रहते हैं, तो यह महान दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है! जब आप अपने चित्त के द्वार ही बंद करके बैठ जाओगे, तो गुरु क्या कर सकता है? गुरु तो उन शिष्यों से मिलने को तरसता है, जो अपनी साधना बिना किसी रुकावट के करते हैं। गुरु को कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। शिष्य तो वही है, जो गुरु के निर्देश, उनके संकेत, उनके भाव समझने में सक्षम हो।

श्री विष्णु पुराण

भक्ति और ज्ञान का अमृत

अठारह पुराण यथा– विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, भविष्य आदि पुराणों में 'श्री विष्णु पुराण' का सर्वोच्च स्थान है। इसके रचयिता श्री पराशर हैं। यह वेदसम्मत पुराण श्री पराशर और श्री मैत्रेय के संवादों में ग्रंथित है। इसमें भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो प्रवाहित है ही, भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्रीकृष्ण चरित्र का अनूठा और विशद वर्णन भी मिलता है। समस्त अध्यायों में कुल मिलाकर 6,310 श्लोक हैं।

इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, मन्वंतर, वंश-चरित, देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, अप्सरा, तपस्वी, मुनि आदि जनों के विशिष्ट चरित, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी, समुद्र, वर्णधर्म, धर्म तथा वेद और शास्त्रों का निरूपण किया गया है।

यह आर्षपुराण शाश्वत है, इसकी परंपरा शाश्वत है। इसके प्रथम अंश में चौबीस तत्वों के साथ जगत के उत्पत्ति-क्रम, विष्णु-महिमा, ब्रह्मादि की आयु, काल का स्वरूप, देवों और दैत्यों द्वारा समुद्रमंथन, ध्रुव की तपस्या, नृसिंहावतार विषयक प्रश्न, प्रह्लादकृत भगवत-स्तुति, भगवान का आविर्भाव तथा भगवान विष्णु की विभूति का वर्णन मिलता है। दूसरे अंश में भारतादि नौ खंडों का विभाग, सात पातालों का वर्णन, भरत-चरित्र, सूर्य नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा नवग्रहों का वर्णन है। तीसरे अंश में सात मन्वंतरों के मनु, सप्तर्षि और मनुपुत्रों का वर्णन, जातकर्म

नामकरण और विवाह संस्कार विधि, श्राद्ध-विधि वर्णित है। चौथे अंश में वैवस्वत मनु-वंश, ययाति-चरित्र, यदु, पुरु और कुरु वंश, कलियुगी राजागण और कलिधर्मों का वर्णन मिलता है।

पांचवें अंश में वसुदेव-देवकी विवाह, कृष्ण का अवतार और लीलाएं आदि वर्णित हैं। छठे अंश के आठवें अध्याय में उपसंहार स्वरूप श्री पराशर ने श्री मैत्रेय को संबोधित करते हुए कहा, 'हे मैत्रेय! मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। इससे कृतार्थ होकर श्री मैत्रेय कहते हैं– भगवन, मुझे जो जानना चाहिए, वह भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत भगवान से भिन्न नहीं है अर्थात सभी भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। 'सर्वे च देवा मनवः समस्ताः सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च। इंदश्च यो यं त्रिदशेशभूतो विष्णोरशेषारतु विभूतयस्ताः॥'

कहना न होगा कि श्री विष्णु पुराण का श्रवण मात्र विपत्तियों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोष दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति प्रदान करने वाला है। इस पुराण का प्रत्येक श्लोक भक्ति और ज्ञान की महत्ता बताता है। इसलिए जो व्यक्ति इसको भक्तिपूर्वक सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली।

डॉ. कल्याण प्रसाद वर्मा

आस्था स्थली : ढिकुली शिवमंदिर, रामनगर, उत्तराखंड

घने वन में पांडवकालीन शिवलिंग

उत्तराखंड स्थित रामनगर, प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। रामनगर-रानीखेत मार्ग पर रामनगर से लगभग नौ किलोमीटर आगे बसा है ढिकुली गांव। गांव से कुछ ही दूर घने जंगल में स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे यहां के स्थानीय निवासी महाभारत के समय का बताते हैं। हालांकि इतिहास के जानकार इसे नौवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच बना बताते हैं। वर्तमान समय में मंदिर का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और अभी यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, आज जिस जगह पर ढिकुली गांव आबाद है, महाभारत के काल में उसी जगह वैराटनगर या विराटनगरी बसी हुई थी। पांडवों ने बारह वर्ष का वनवास पूर्ण होने के बाद विराटनगरी में ही विराट नरेश के सेवकों के रूप में एक वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। यह भी कहा जाता है कि क्षेत्र में कत्यूरी वंश के राजाओं के प्रभावी होने से पहले यहां कुरुवंशी नरेशों का आधिपत्य था, जिन्हें प्राचीन इंद्रप्रस्थ साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त था।

रानीखेत रोड के एक ओर ढिकुली है तथा दूसरी ओर कॉर्बेट पार्क का जंगल है, जहां लगभग 500 मीटर की पैदल दूरी पर यह मंदिर स्थित है। जैसे ही आप सड़क से इस जंगल का रुख करते हैं, आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे जाता है, जिसके अनुसार यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। बोर्ड पर इस स्थान का नाम वैराटपट्टन लिखा है।

मंदिर-क्षेत्र में पहुंचने पर सबसे पहले गर्म जल की एक धारा तथा सामने प्रतिष्ठित विशाल शिवलिंग दिखाई पड़ता है। इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। मंदिर में एक

स्थान पर कुछ पुरानी खंडित मूर्तियां भी रखी हुई हैं, जो यहां खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थीं। मंदिर के पुजारी बाबा मंगलदास बताते हैं कि इस शिवलिंग के नीचे एक भूमिगत जलधारा मौजूद है। वास्तव में मंदिर-परिसर के आस-पास प्रचुर मात्रा में जलस्रोत हैं।

ढिकुली जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित गर्जिया देवी के मंदिर जाना भी एक यादगार अनुभव होगा। कोसी नदी के बीच एक टीले पर स्थित यह मंदिर भी प्राचीन है, हालांकि इसका मौजूदा स्वरूप नया है।

कैसे पहुंचें : देश के प्रमुख शहरों से ट्रेन के जरिये रामनगर जा सकते हैं। वहां से स्थानीय यातायात साधनों से आसानी से ढिकुली पहुंच सकते हैं।□□□

दिनेश चंद्र पाठक

टीवीएस अपाचे RTR 160 4V और RTR 200 4V का BS6 वेरियंट लॉन्च

नई दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी ने मंगलवार को इंडियन मार्केट में 2020 अपाचे RTR 160 4V और Apache RTR 200 4V लॉन्च की हैं। दोनों ही बाइक में BS6 नॉर्म्स के मुताबिक इंजन और एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स टीवीएस मोटर कंपनी की लाइनअप में पहले प्रॉडक्ट्स हैं, जिन्हें नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। टीवीएस की इन दोनों बाइक्स में BS6 कंप्लायंट इंजन के अलावा LED हेडलैंप और नए डिजाइन किए गए पोजिशन लैंप्स दिए गए हैं। इसके अलावा, दोनों बाइक्स में ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक (GTT) राइडिंग मोड भी दिया गया है।

99,950 रुपये है शुरुआती कीमत

2020 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V ड्रम और डिस्क इन दो वेरियंट्स में आ रही है। ड्रम वेरियंट की कीमत 99,950 रुपये है। वहीं, इसके डिस्क वेरियंट की कीमत 1.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम प्राइस) है। 2020 टीवीएस अपाचे RTR 200 4V की कीमत 1.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम प्राइस) है। 2020 अपाचे सीरीज में TVS का RT-Fi फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। पुराने BS4 वर्जन के मुकाबले BS6 कंप्लायंट टीवीएस अपाचे RTR 160 4V का डिस्क वेरियंट करीब 3,000 रुपये महंगा है। वहीं, ड्रम वेरियंट में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नॉलजी दी गई है, जिसके कारण यह पुराने मॉडल के मुकाबले करीब 8,000 रुपये महंगी है। जबकि BS6 कंप्लायंट टीवीएस अपाचे RTR 200 4V की कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले 10 हजार रुपये बढ़ी है।

दोनों बाइक्स में है लो-स्पीड राइडिंड मोड GTT

दोनों ही बाइक्स में नया लो-स्पीड राइडिंड मोड GTT दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कंट्रोल्ड और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। टीवीएस की यह दोनों बाइक नई LED हेडलाइट, नई तरीके से डिजाइन किए गए मिरर्स और फेदर टच स्मार्ट के साथ आती हैं। 2020 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V में BS6 कंप्लायंट 159.7cc का सिंगल सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो कि 16.02 PS का पावर और 14.12Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

चालू हुई इन बाइक्स की बुकिंग

वहीं, 2020 टीवीएस अपाचे RTR 200 4V ceW BS6 कंप्लायंट 197.75cc का सिंगल सिलिंडर, ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स है। इंजन 20.5PS का पावर और 16.80Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह बाइक ग्लास ब्लैक और पर्ल व्हाइट इन 2 कलर में उपलब्ध होगी। वहीं, 2020 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V बाइक रेसिंग रेड, मेटलिक ब्लू और नाइट ब्लैक कलर में उपलब्ध होगी। टीवीएस मोटर कंपनी की सभी डीलरशिप्स में इन मोटरसाइकिल्स की बुकिंग चालू हो गई है।टीवीएस अपाचे RTR 160 4V और RTR 200 4V और BS6 वेरियंट लॉन्च।

सबसे सस्ती कार Kwid में अब जल्द मिलेगा Bs6 इंजन

जानें क्या कुछ होगा नया

नई दिल्ली। Renault भारतीय बाजार में अपनी सबसे किफायती कार Kwid का अब बीएस-6 वेरिएंट लेकर आने वाली है। भारत में Kwid सबसे सस्ती स्टाइलिश कार मानी जाती है। अब इस कार में बीएस-6 इंजन आने के बाद इसके माइलेज में थोड़ी कमी आएगी और साथ ही साथ इसकी कीमत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान में Renault Kwid दो इंजन के विकल्प में आती है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो Kwid में रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर, ड्राइवर एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, ड्राइवर और पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑवरस्पीड अलर्ट, फ्रंट सीट इंटीग्रेटिड हैडरेस्ट, रियर सीट इंटीग्रेटिड नेक रेस्ट, रियर ईएलआर सीट बेल्ट, रियर चाइल्ड डोर लॉक, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पेयर व्हील, एलईडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल टेक्नोमीटर, ऑन बोर्ड ट्रिप कंप्यूटर, गियर शिफ्ट इंडीकेटर जैसे फीचर्स दिए हैं। इसमें 799cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन है जो कि 5678 Rpm पर 54 Ps की पावर और 4386 Rpm पर 72 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 1.0 लीटर का स्मार्ट कंट्रोल एफिशिएंसी इंजन है जो कि 5500 Rpm पर 68 Ps की पावर और 4250 Rpm पर 91 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो Renault Kwid के फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सस्पेंशन की बात की जाए तो Renault Kwid के फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद लॉवर ट्रांसवर्से संस्पेंशन दिया गया है और रियर में कॉइल स्प्रिंग के साथ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन दिया गया है। डाइमेंशन के मामले में Renault Kwid की लंबाई 3731 mm, चौड़ाई 1579 mm, ऊंचाई 1490 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 184 mm, व्हील बेस 2422 mm और 28 लीटर का फ्यूल टैंक है। कीमत की बात की जाए तो Renault Kwid की एक्स शोरूम कीमत 283290 रुपये से 492190 रुपये (दिल्ली एक्स शोरूम) तक है।

भारत-अमेरिका ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए 40 सामानों की पहचान की

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत और अमेरिका ने करीब 40 ऐसे सामानों की पहचान की है, जिन्हें आयात शुल्क से छूट दी जा सकती है। इनमें पिस्ता, काजू और सेब शामिल हैं। दोनों देश मेडिकल डिवाइसेज पर व्यावहारिक रियायतों को जीरो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते दोनों देशों के कारोबार मध्यस्थों के बीच आधिकारिक स्तर की मुलाकात में इन पर बात हुई। हालांकि इस दौरान डेयरी आयात पर कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक 'चर्चाएं ज्यादातर एग्री प्रॉडक्ट्स को लेकर हुई हैं।' अमेरिका ने भारत से दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की भी मांग की है। उसने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत की तरफ से कुछ दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन से शिकायत की थी। भारत ने यह बैन घरेलू बाजार में दाल की गिरती कीमतों को रोकने के लिए लगाया था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारत को अमेरिका से पिस्ता का आयात बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से एक ने कहा, 'वार्ता धीमी रफ्तार से बढ़ रही है।' वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 दिन पहले अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर और अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेज के प्रतिनिधियों से अमेरिका में मुलाकात की थी। इसके बाद ही यह कदम उठाया गया है। रॉबर्ट जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेज की कीमतें और डेयरी इंपोर्ट्स कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें दोनों देश सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। गोयल ने कहा था कि हमें किसान समुदाय के साथ ही धार्मिक संवेदनाओं का भी ख्याल रखना है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में ऐसे प्रॉडक्ट्स जिनके फूड चेन में पशु चारा होगा, उनके आयात में कोई समझौता नहीं करेंगे। डेयरी उन सेक्टर्स में से एक है, जिसे ण्ड्रिं ट्रेड अग्रीमेंट में शामिल करने का भारत ने कड़ा विरोध किया था। लंबी बातचीत के बाद भारत ने फिलहाल इस समझौते से नहीं जुड़ने का फैसला किया है। एक्सपर्ट्स ने भारत-अमेरिका के बीच आगे बढ़ी वार्ता को ट्रेड पैकेज की दिशा में शुरुआती कदम बताया है। ट्रेड मुद्दों के एक जानकार ने कहा, 'यह एक अच्छी प्रगति है क्योंकि दोनों के कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं। जिस तरह दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, उस आधार पर एक या दो महीनों के अंदर एक ट्रेड पैकेज तय किया जा सकता है।'

रिजर्व बैंक ने मुद्रा योजना के तहत बढ़ते फंसे कर्ज पर चिंता जताई

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम के जैन ने मंगलवार को छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई मुद्रा रिण योजना में कर्ज वसूली की बढ़ती समस्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बैंकों से कहा कि वह इस योजना के तहत दिये जाने वाले कर्ज पर करीबी नजर रखें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मुद्रा कर्ज योजना की शुरुआत की थी। यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जरूरी वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई है। जैन ने यहां भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सूक्ष्म वित्त पर आयाजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा, ''मुद्रा योजना पर हमारी नजर में है ... इस योजना से जहां एक तरफ देश के कई लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में बड़ी मदद की हो वहीं इसमें कई कर्जदारों के बीच गैर- निष्पादित राशि के बढ़ते स्तर को लेकर कुछ चिंता भी है।''

शहद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों के बीच एनएमआर जांच पर बनी सहमति

नयी दिल्ली। शहद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) से कहा है कि वह निर्यात किए जाने वाले शहद की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एनएमआर जांच को अनिवार्य करे। एनएमआर (परमाणु चुम्बकीय प्रतिध्वनि) जांच के जरिये शहद के उत्पादन स्थल, उसमें किसी भी तरह की मिलावट, उसमें विभिन्न पोषक अवयवों की उपलब्धता आदि की गहन जांच की जाती है और इस परीक्षण से गुजरने के बाद निर्यात पर शहद के लिए अच्छे दाम मिलते हैं। शहद उद्योग के प्रतिनिधियों के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार (एपिडा) की बैठक में 18 नवंबर को शहद निर्यातकों की एक बैठक बुलाई गई और उसी दिन शहद निर्यातक संघ का गठन किया गया। इस बैठक में सभी निर्यातकों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि एनएमआर जांच को अनिवार्य किया जाये। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य देवव्रत शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''अभी ईआईसी ने मुंबई के पास एक प्रयोगशाला की स्थापना की है जिसमें अभी सिर्फ निर्यात खेप वाले शहद के नमूनों की जांच की व्यवस्था है लेकिन आम किसानों को यह सुविधा हासिल नहीं है। दो वर्ष पहले निर्यातकों को जहां शहद के लिए 2,900 डॉलर प्रति टन के दाम मिलते थे वहीं मिलावटी शहद के कारण अब 1,500 डॉलर के आसपास भाव मिलने लगा है। लेकिन एनएमआर जांच से गुजरने के बाद विदेशों में हमारे सामान की गुणवत्ता और उसकी साख बढ़ेगी । इससे निर्यात बढ़ेगा और दाम भी अच्छे मिलेंगे।'' उन्होंने बताया, ''पिछले साल 62,000 टन शहद का निर्यात हुआ था। हमें शहद के लिए 1,500 डॉलर प्रति टन का भाव मिला। लेकिन उम्मीद है कि एनएमआर जांच वाले शहद के लिए हमें फिर से लगभग 2,000 डॉलर प्रति टन से अधिक का भाव मिलना शुरु होगा।'' शहद निर्यातक संघ के अध्यक्ष प्रकाश केजरीवाल, जो निर्यातक भी हैं, ने कहा, ''भारत का शहद अर्जेन्टीना, ब्राजील, उक्रेन जैसे निर्यातक देशों के पहले आ जाता है और देश से विशेषकर सरसों फूल से बने शहद का निर्यात किया जाता है जिसकी विदेशों में भारी मांग है। अजवाइन, लीची, युकिलिप्टस, जामुन वह अन्य फूलों से बने शहद की घरेलू स्तर पर ही खपत हो जाती है। किसानों को उनके उत्पाद के लिए 65 से 75 रुपये प्रति किलो के दाम मिलते हैं। एनएमआर जांच के बाद विदेशों में हमें अच्छे दाम मिलने पर निर्यातकों में किसानों को 85 रुपये प्रति किलो का दाम देने के बारे में भी सहमति बनी है।'' आंकड़ों के अनुसार, भारतीय शहद के 80 प्रतिशत का निर्यात अमेरिका को होता है जबकि 19 प्रतिशत निर्यात पश्चिम एशियाई देशों को और एक प्रतिशत निर्यात यूरोपीय देशों को होता है।

www.eng-expo.co.in
www.eng-expo.in

Why Should You
Participate in Madhya Pradesh ?

- Explore the unexplored opportunities.
- Biggest automobile hub in India.
- Most flourishing food and grain industry.
- Industrial Development on a rapid pace in Plastic Parks, Textile Parks, SEZs, Pharma Zones.
- Both IIMs and IITs are here
- Cleanest city of India third time in a row (IT'S A HATTRICK).
- Fast infrastructure development.
- Centrally connected transport system.
- Good, peaceful and conducive atmosphere for business development.
- Well equipped communication network.
- Proactive initiatives by the state government.

Central India's Largest SME Exhibition

Industrial ENGINEERING EXPO

CONCURRENT EVENTS

3rd International Industry & Technology Expo

PLAST PACK & PRINT EXPO 2019

ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2019

INDORE 20 21 22 23 DEC 2019

LABHGANGA EXHIBITION CENTRE

SPONSORED BY

CO-SPONSORED BY

ORGANISED BY

CONCURRENT EVENT ORGANISED BY

SPONSORED BY

SUPPORTED BY

For Participation Call

9826887800, 9826497000, 9981224262, 9827044408

futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।